न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 53/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/00244

बउनवानी:—हरिसिंह पुत्र केसरा उर्फ केसरलाल जाति मीना निवासी नीमली तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 356/2017 निर्णय दिनांक 8.2.2017 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री पारस मल जैन वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 13.5.2019

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 356/2017 में पारित निर्णय दिनांक 8.2.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2073 में वाके ग्राम नीमली कलां की बारीन 2 भूमि आराजी ख0न0 487 रकबा 0.85 है0 पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2071 के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है क्योकि ख0न0 787 रकबा 0.40 है0 पर अपीलान्ट का काफी समय से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि को नियम करवाने का अधिकारी है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के कियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है क्योंकि पटवारी हल्का के बयान के प्रिन्टेड फार्म मे पटवारी द्वारा अपनी जाति व पिता का नाम तक भी गलत अंकित किया गया है जिसके कारण अपीलान्ट के विरूद्व की गयी कार्यवाही पर भी सन्देह किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.3..2017 को पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर गांव आने पर घरवालो के बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार जावे एंव आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की व्यक्तिशः करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जहॉ तक पटवारी बयान फार्म पर पटवारी की जाति व पिता का नाम गलत होने का प्रश्न है तो मानवीय भूलवश सम्भव हो सकता है किन्तु इस बाबत संबंधित पटवारी से शपथ पत्र लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट की व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 के आधार पर हो जाती है। चूॅकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नही किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ति अतिचार साबित नही होता हो। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने तथा सुनवायी का समुचित अवसर तथा पटवार हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया जाने बाबत कथन किया गया है। जहॉ तक पटवारी बयान फार्म पर पटवारी की जाति व पिता का नाम गलत होने का प्रश्न है तो इस संबंध में संबंधित पटवारी से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है जो पटवार बयान के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल मे शामिल किया गया है। किन्तु न्याय के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना व संबंधित पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया जाना उचित समझता हूॅ। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अपीलान्ट को पुनः सुनवायी का अवसर दिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध मौके की जॉच कर एवं अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.5..2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:31:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: